Distribution of Rotten Rice in Calcutta

119. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the West Bengal Food Minister has made the allegation that Centre wants to distribute 20 lakh tonnes of rotten rice from its stock in Calcutta;

(b) whether there is any truth in the allegation; and

(c) the reaction of the Government to the allegation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). No, Sir. The total quantity of rice as on 1st September 1977 in West Bengal Region in the godowns of the Food Corporation of India was 2-19 lakh tonnes out of which only a quantity of 0.11 lakh tonnes was in lower category.

In July, 1977 a complaint about the quality of rice being supplied by Food Corporation of India was, however, received from the West Bengal Government. This was immediately investigated jointly by a team of officials of Central Government, State Government and the F.C.I. to ensure only Fair Average Quality of foodgrains are issued for Public distribution system. A system of joint inspection with the State Government has been introduced so as to ensure good quality of stocks.

The allegations are, therefore unfounded.

कुओं के खारेपन से संरक्षण के लिये केन्द्रीय सहायता

120. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनी से पोरबन्दर, माधवपुर, शील, मंगरोल, चीडुवाद, वैरावल, कौडिनार, उना, राजूला और माबूवा तक समुद्र तट से दो से छः किलोमीटर की दूरी के अन्दर किसानों के कुओं का जल खारा हो गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने कुएं हैं और कृषि भूमि का कितना क्षेत्र क्षारीय हो गया है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इन कुओं और भूमि के संरक्षण के लिये तथा इस जल को मीठे जल में बदलने के लिये कोई योजना बनाई है और केन्द्रीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो कब और इसका स्वरूप और मात्रा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) जी हां। गुजरात सरकार ने लगभग 16000 कुओं और 600 वर्ग कि० मीटर कृषि भूमि के क्षारीय होने की सूचना दी है।

(ख) और (ग) . राज्य सरकार द्वारा 92.7 लाख की अनुमानित लागत से गुजरात में लवणता का कृत्रिम रूप में रिचार्ज तथा नियंत्रण करने के लिए एक मार्गदर्शी योजना बनाई गई जिसकी केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल द्वारा जांच की गई और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों ने इस पर 2 सितम्बर, 1977 को विचार विमर्श भी किया। यह स्वीकार किया गया था कि गुजरात सरकार द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों में संशोधन करने की